रणजीत टाइम्स

इंदौर

शनिवार , 18 अप्रैल, 2026

वर्ष 02 | अंक 98 कुल पृष्ठ : 8 | Digital

RNI-NO.MPHIN/2015/64585

प्रधान संपादक : गोपाल गावंडे

राज्यसभा के उपसभापति चुने गए

हरिवंश नारायण सिंह

राज्यसभा में हरिवंश नारायण सिंह को एक बार फिर उपसभापति चुना गया है। यह उनका लगातार तीसरा कार्यकाल है, और खास बात यह है कि इस बार भी उनका चयन बिना किसी विरोध या मतदान के निर्विरोध हुआ। भारतीय संसदीय इतिहास में यह एक उल्लेखनीय स्थिति मानी जा रही है, जब किसी उम्मीदवार को लगातार तीसरी बार इस पद के लिए बिना प्रतिस्पर्धा चुना गया हो।

PM मोदी रहे मौजूद-इस प्रक्रिया के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सदन में मौजूद रहे, जिससे इस चुनाव की राजनीतिक और संवैधानिक अहमियत और बढ़ गई। उनकी उपस्थिति ने यह संकेत भी दिया कि यह सिर्फ एक औपचारिक चुनाव नहीं था, बल्कि संसदीय कार्यप्रणाली में सहमति और संतुलन का महत्वपूर्ण क्षण था।

राज्यसभा उपसभापति का कार्य- राज्यसभा उपसभापति का पद संसद की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में हरिवंश नारायण सिंह का लगातार तीसरी बार इस पद पर निर्विरोध चुना जाना, उनके प्रति सदन के अधिकांश सदस्यों के विश्वास को भी दर्शाता है।

बिना उम्मीदवार के हुआ चुनाव- इस चुनाव में विपक्ष की ओर से कोई भी उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा गया। इसके चलते पूरा चुनावी परिदृश्य पहले ही लगभग तय माना जा रहा था। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह स्थिति कभी-कभी रणनीतिक सहमति का परिणाम होती है, तो कभी विपक्ष की सीमित राजनीतिक मजबूती का संकेत भी देती है। हालांकि, इस बार का दृश्य यह भी दिखाता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कुछ मामलों में सहमति का माहौल भी बन सकता है, खासकर जब संसदीय परंपराओं और संस्थागत पदों की बात आती है।

तीसरा निर्विरोध चयन- हरिवंश नारायण सिंह

का यह लगातार तीसरा निर्विरोध चयन भारतीय लोकतंत्र में एक दुर्लभ उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। यह न केवल उनकी व्यक्तिगत राजनीतिक स्वीकार्यता को दर्शाता है, बल्कि राज्यसभा की कार्यसंस्कृति में स्थिरता और निरंतरता का संकेत भी देता है। कुल मिलाकर, यह चुनाव संसदीय राजनीति में एक ऐसे क्षण के रूप में दर्ज हुआ है, जहां प्रतिस्पर्धा की जगह सहमति और संतुलन ने प्रमुख भूमिका निभाई।

प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई- इस पूरी प्रक्रिया के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सदन में मौजूद रहे। उन्होंने हरिवंश नारायण सिंह को बधाई दी।

'ज़िंदा हैं मोजतबा खामेनेई लेकिन बुरी तरह जख्मी', अमेरिकी युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ का दावा

ईरान और अमेरिका के बीच 8 अप्रैल को लागू हुआ सीज़फायर 21 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। ऐसे में स्थायी समझौते के लिए दोनों पक्ष कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि ईरान से जल्द ही समझौता हो जाएगा। ईरान के खिलाफ जब से जंग की शुरुआत हुई, तब से अब तक देश के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। अलग-अलग मौकों पर मोजतबा की मौत की अफवाह सामने आई हैं, जिसे ईरान ने नकार दिया है। अब अमेरिका के युद्ध मंत्री (रक्षा मंत्री) पीट हेग्सेथ ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर के बारे में बयान दिया है।

ज़िंदा हैं मोजतबा खामेनेई लेकिन बुरी तरह जख्मी'

मोजतबा के बारे में हेग्सेथ ने दावा किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर ज़िंदा हैं, लेकिन वह बुरी तरह से जख्मी हैं। युद्ध की शुरुआत के कुछ समय बाद से ही ये खबरें आ रही हैं कि मोजतबा ज़िंदा तो हैं लेकिन अमेरिकी-इज़रायली हमलों में उन्हें काफी चोट आई हैं और उनका इलाज चल रहा है। हालांकि ईरान की तरफ से हमेशा कहा गया है कि उनके सुप्रीम लीडर स्वस्थ हैं।

कहाँ हैं मोजतबा?

मोजतबा कहाँ हैं, इस बारे में ईरान में मौजूद रूस (Russia) के राजदूत ने कुछ समय पहले जवाब दिया था। उन्होंने बताया था कि मोजतबा ईरान में ही हैं, लेकिन सुरक्षित जगह पर हैं। कुछ समय पहले यह खबर भी आई थी कि ईरान के कोम शहर में मोजतबा का इलाज चल रहा है।

अमेरिका-इज़रायल तलाश में

खतरे की स्थिति को देखते हुए मोजतबा किसी बेहद ही खुफिया और सुरक्षित स्थान पर छिपे हुए हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका और इज़रायल उनकी तलाश में जुटे हुए हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए और इज़रायली खुफिया एजेंसी मोसाद (Mossad) के जासूस मोजतबा को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई है। अमेरिका और इज़रायल ने मोजतबा को मारने के लिए कई बार खुफिया सूचना के आधार पर ईरान में हर उस जगह हमले किए जहाँ मोजतबा के होने की उम्मीद थी, लेकिन वह हर बार अपनी जान बचाने में कामयाब रहे।

बिहार: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के समक्ष चुनौतियों का अंबार

बिहार की राजनीति में आए बड़े बदलाव के साथ ही सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की कमान संभाल ली है। हालांकि, सत्ता का यह सिंहासन उनके लिए सुखद अनुभव से अधिक 'कांटों भरा ताज' सिद्ध हो रहा है।

एक ओर जनता से किए गए बड़े वादों का भारी बोझ है, तो दूसरी ओर राज्य का रिक्त होता सरकारी खजाना उनके सामने हिमालय जैसी चुनौतियां खड़ी कर रहा है। बिहार के नवनियुक्त मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऐसे समय में सत्ता संभाली है जब राज्य एक गंभीर आर्थिक संकट और प्रशासनिक असमंजस के चौराहे पर खड़ा है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि सम्राट चौधरी के लिए आगामी समय किसी कठिन परीक्षा से कम नहीं होगा।

1 रिक्त राजकोषः सबसे बड़ी बाधा

बिहार की आर्थिक स्थिति वर्तमान में अत्यंत नाजुक मोड़ पर है। पिछले कुछ वर्षों में राज्य के राजस्व संग्रहण में गिरावट आई है और केंद्र पर निर्भरता बढ़ी है। मुख्यमंत्री के सामने पहली बड़ी चुनौती दैनिक प्रशासनिक व्यय और विकास कार्यों के बीच संतुलन बैठाना है। चुनावों और गठबंधन की राजनीति के दौरान जनता से अनेक लोक-लुभावन वादे किए गए हैं। रोजगार सृजनः युवाओं को दी गई सरकारी नौकरियों की गारंटी को पूरा करना सबसे प्राथमिकता वाला कार्य है। सामाजिक कल्याण योजनाएंः वृद्धावस्था पेंशन, शिक्षा सहायता और महिला सशक्तिकरण की योजनाओं के लिए भारी धन राशि की आवश्यकता है।

3 प्रशासनिक सुधार और सुशासन

लंबे समय से चली आ रही सुस्त प्रशासनिक व्यवस्था में प्राण फूंकना सम्राट चौधरी के लिए अनिवार्य है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुँचाना उनके नेतृत्व की असली पहचान होगी।

चुनौतियों से निपटने की संभावित रणनीति

विशेषज्ञों के अनुसार, नए मुख्यमंत्री निम्नलिखित मार्गों से इन संकटों का समाधान खोज सकते हैंः केंद्रीय सहायता की आसः केंद्र सरकार से 'विशेष पैकेज' या अतिरिक्त वित्तीय सहायता के लिए प्रयास करना। निवेश प्रोत्साहनः बिहार में उद्योगों को आकर्षित करने के लिए नई नीति बनाना ताकि निजी निवेश के माध्यम से रोजगार बढ़े और राजस्व प्राप्त हो।

व्यय में कटौती

अनावश्यक सरकारी खर्चों को कम कर उस धन को कल्याणकारी योजनाओं में लगाना। सम्राट चौधरी के सिर पर रखा गया यह ताज निश्चित रूप से कांटों भरा है। उनके पास समय कम है और अपेक्षाएं बहुत अधिक। यदि वे इन आर्थिक और राजनैतिक चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं, तो वे न केवल अपनी स्थिति सुदृढ़ करेंगे, बल्कि बिहार के विकास को एक नई दिशा भी दे सकेंगे। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं

BJP मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में नियुक्तियां कब होंगी? बंद कमरे की बैठक में क्या हुआ...बड़ा अपडेट आया सामने

उत्तर प्रदेश में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार और भाजपा प्रदेश संगठन में बड़े बदलावों को लेकर अब दिल्ली में मंथन तेज हो गया है। गुरुवार को राजधानी में एक अहम बैठक आयोजित हुई, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह (ने पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ लंबी चर्चा की।

बंद कमरे की बैठक में क्या हुआ?- इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और बीएल संतोष भी शामिल रहे। बैठक बंद कमरे में हुई, जिसमें प्रदेश के राजनीतिक समीकरणों और संगठनात्मक ढांचे पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

यूपी BJP मंत्रिमंडल को लेकर इस सप्ताह हो सकता है अंतिम फैसला- बंद कमरे में हुई बैठक के बाद ये संकेत मिल रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में बदलाव के स्वरूप को इसी सप्ताह अंतिम रूप दिया जा सकता है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, इन दोनों स्तरों पर होने वाले बदलावों के लिए अगले सप्ताह की शुरूआत के पहले 2-3 दिन बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। संभावना जताई जा रही है कि रविवार (19 अप्रैल) या

सोमवार (20 अप्रैल) को मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। इसके तुरंत बाद संगठन में नए पदाधिकारियों की सूची भी जारी कर दी जाएगी।

लखनऊ में भी हुई थी गहन चर्चा- इससे पहले भाजपा संगठन चुनाव के प्रेक्षक विनोद तावड़े ने हाल ही में दो दिनों तक लखनऊ में प्रवास किया था। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री, दोनों उपमुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ कई दौर की बैठकें कीं। इन बैठकों में मंत्रिमंडल विस्तार, संगठनात्मक बदलाव के साथ-साथ निगमों और बोर्डों में नियुक्तियों को लेकर भी रायशुमारी की गई। विभिन्न नेताओं से फीडबैक लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई।

अमित शाह को सौंपी गई रिपोर्ट- विनोद तावड़े ने अपनी रिपोर्ट पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सौंप दी है। यह रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्री और पार्टी अध्यक्ष को दी गई, जिसके आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाना है। सूत्रों का कहना है कि अब इसी रिपोर्ट के आधार पर अंतिम दौर की बैठकों में निर्णय तय किए जा रहे हैं, ताकि सभी राजनीतिक और संगठनात्मक संतुलन बनाए रखे जा सकें।

अंतिम फैसले से पहले फिर होगी मुलाकात- सूत्रों के मुताबिक, शुक्रवार या शनिवार को प्रदेश के शीर्ष पदाधिकारी एक बार फिर अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। इस बैठक के बाद मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में बदलाव को लेकर अंतिम मुहर लगने की संभावना है।

राजनीतिक हलकों में बढ़ी हलचल- इन बैठकों और संभावित फैसलों को लेकर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में बदलाव को लेकर विभिन्न स्तरों पर कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इन फैसलों से आने वाले समय में पार्टी की रणनीति और राजनीतिक समीकरणों पर बड़ा असर पड़ेगा।

डॉ आंबेडकर का पोस्टर फाड़कर पैरों से कुचलने वालों के विरुद्ध,थाने मे दिया आवेदन

दिव्यानंद अर्गल

ग्वालियर I विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिंधिया नगर भरघट पहाड़िया इलाके में डॉ. भीमराव अंबेडकर के पोस्टर को फाड़ने और अपमान करने के मामला सामने आया है। इस घटना के बाद स्थानीय निवासियों में भारी रोष व्याप्त है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। सिंधिया नगर में बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर का पोस्टर लगा हुआ था।

आरोप है कि इंद्रवीर नामक व्यक्ति के यहां पारिवारिक समारोह चल रहा था जिसमें उनके रिश्तेदार द्वारा इस पोस्टर को फाड़ दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आरोपियों ने न केवल पोस्टर फाड़ा, बल्कि उसे पैरों से कुचला भी। इस पूरी घटना को स्थानीय युवक ने अपनी आंखों से देखा। बताया जा रहा है कि घटना के पुख्ता सबूत पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गए हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि जब उन्होंने इस अपमानजनक कृत्य का विरोध किया, तो आरोपियों ने उनके साथ अभद्रता की और उन्हें जातिसूचक गालियां दीं। घटना के बाद से दलित समुदाय के लोगों में गहरा आक्रोश है। आजाद समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव रायसिंह बौद्ध ने बताया कि इस संबंध में विश्वविद्यालय थाने में लिखित आवेदन दिया है जिसमें इस घटना में जो भी लोग शामिल हैं उन सभी आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की मांग की है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

कलेक्टर शिवम वर्मा ने स्वयं भरा ऑनलाइन स्व-गणना फार्म

आदित्य शर्मा

नागरिकों से जनगणना के कार्य में सहयोग की अपील की शुरू हुई जनगणना सेल्फ इन्यूमरेशन प्रक्रिया के तहत कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने स्वयं ऑनलाइन स्व-गणना (Self Enumeration) फॉर्म भरकर नागरिकों को प्रेरित किया। कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि जनगणना देश की विकास योजनाओं की आधारशिला है, इसलिए प्रत्येक नागरिक को इसमें सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने इंदौरवासियों से अपील की कि वे जनगणना पोर्टल पर जाकर स्वयं अपनी जानकारी दर्ज करें और इस प्रक्रिया को सरल व पारदर्शी बनाने में सहयोग दें। श्री वर्मा ने बताया कि सेल्फ इन्यूमरेशन से समय की बचत होगी और जब टीम घर-घर पहुंचेगी, तब प्रक्रिया और भी आसान हो जाएगी। कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने नागरिकों से आग्रह किया कि वे https://se.census.gov.in पर जाकर अपनी जानकारी दर्ज करें। नागरिकों के लिये पोर्टल पर स्व-गणना का कार्य 16 अप्रैल से प्रारंभ किया गया है जो 30 अप्रैल तक उपलब्ध रहेगा। स्व-गणना की पूरी प्रक्रिया सुरक्षित है और इसे हिंदी, अंग्रेजी सहित 14 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है, ताकि हर वर्ग के लोग आसानी से इसका उपयोग कर सकें। इसमें 5 से 10 मिनट में स्व-गणना की पूरी प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। कलेक्टर श्री वर्मा ने नागरिकों से अपील की है कि इस सुविधा का अधिकतम लाभ उठायें और जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें।

रणजीत टाइम्स

सड़क सुरक्षा समिति की बैठक सम्पन्न

आदित्य शर्मा

सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य श्री संजय बंदोपाध्याय विशेष रूप से हुए शामिल

इंदौर इंदौर जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आज कलेक्टर कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में सड़क सुधार एवं यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से समीक्षा की गई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य श्री संजय बंदोपाध्याय (सेवानिवृत्त आईएएस) विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में कलेक्टर श्री शिवम वर्मा, डीसीपी ट्रैफिक श्री राजेश त्रिपाठी, अपर कलेक्टर श्री रोशन राय, अपर आयुक्त नगर निगम श्री आकाश सिंह, श्री प्रखर सिंह, श्री अभय राजनगांवकर सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

बैठक में श्री संजय बंदोपाध्याय ने कहा कि सड़क एवं यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए इंफोर्समेंट और जन-जागरूकता पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान सहित अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों की मदद लेकर सड़क सुधार कार्यों में तेजी लाई जाए तथा बड़े शहरों के सफल नवाचारों को साझा किया जाए। उन्होंने ब्लैक स्पॉट के सुधार पर विशेष फोकस करने, सड़क दुर्घटना होने पर तत्काल पोर्टल पर जानकारी दर्ज करने और तुरंत एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। साथ ही कार्यों को परिणाममूलक बनाने, यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालानी कार्रवाई को तेज करने तथा चालान प्रक्रिया में एआई जैसी अत्याधुनिक तकनीकों के उपयोग पर भी जोर दिया बैठक में जिले में पिछले पांच वर्षों के दौरान हुई सड़क दुर्घटनाओं, मृत्यु एवं घायलों की संख्या का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया। ब्लैक स्पॉट्स के डेटा, उनकी वर्तमान स्थिति तथा किए गए सुधार कार्यों के प्रभाव पर भी विस्तृत चर्चा की गई। सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में जिले में किए जा रहे नवाचार एवं श्रेष्ठ अभ्यासों की जानकारी दी गई। साथ ही सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किए गए भौतिक एवं इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपायों की समीक्षा की गई। राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर स्थित प्रमुख ब्लैक स्पॉट्स के निरीक्षण एवं सुधार कार्यों की प्रगति पर भी चर्चा हुई।

इंदौर सम्राट दंगल 19 अप्रैल को

अमन पहलवान और मोहित कुंदु के बीच होगी मुख्य कुश्ती

खुशबू श्रीवास्तव

इंदौर। शहर में पारंपरिक खेल कुश्ती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंदौर सम्राट दंगल का भव्य आयोजन 19 अप्रैल 2026, रविवार को किया जा रहा है। यह आयोजन दोपहर 3:00 बजे से कुम्हारखाड़ी कुश्ती स्टेडियम, बाणगंगा, इंदौर में आयोजित होगा। श्री बलभीम व्यायामशाला बाणगंगा के तत्वावधान में आयोजित यह दंगल स्वर्गीय द्वारका प्रसाद जी पाल, गोपाल पहलवान, टोटेलाल जी ठाकुर एवं बहादुर सिंह जी ठाकुर की स्मृति में किया जा रहा है।

दंगल का मुख्य आकर्षण अमन पहलवान और मोहित कुंदु के बीच होने वाली रोमांचक कुश्ती रहेगी, जिसे देखने के लिए शहर सहित आसपास के क्षेत्रों के कुश्ती प्रेमियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। आयोजन के संरक्षक अर्जुन जी ठाकुर पहलवान हैं, जबकि धीरज जी ठाकुर पहलवान मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहे हैं। इसके साथ ही दीपू यादव जी और बंटी खलीफा आयोजन में विशेष सहयोग प्रदान कर रहे हैं।

इस दंगल में प्रदेश एवं देश के विभिन्न हिस्सों से आए कई नामी पहलवान भाग लेंगे, जिससे दर्शकों को रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे। आयोजकों ने शहरवासियों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस पारंपरिक खेल का आनंद लें और पहलवानों का उत्साहवर्धन करें।

इंदौर आबकारी में इतिहास: पहली बार 2100 करोड़ पार, सभी 173 दुकानें नीलाम

आदित्य शर्मा

सह संपादक रणजीत टाइम्स

इंदौर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सुशासन, पारदर्शिता एवं राजस्व सुदृढ़ीकरण के विज़न के अनुरूप तथा कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के मार्गदर्शन में इंदौर आबकारी विभाग द्वारा वर्ष 2026–27 हेतु मदिरा दुकानों के निपटान की ई-टेंडर प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली गई है। जिले में कुल 77 समूह (47 समूह एवं 30 एकल दुकानें) की 173 मदिरा दुकानों का शत-प्रतिशत निष्पादन सुनिश्चित करते हुए 2184.76 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया गया है, जो कि इंदौर जिले में अब तक का सर्वाधिक है।

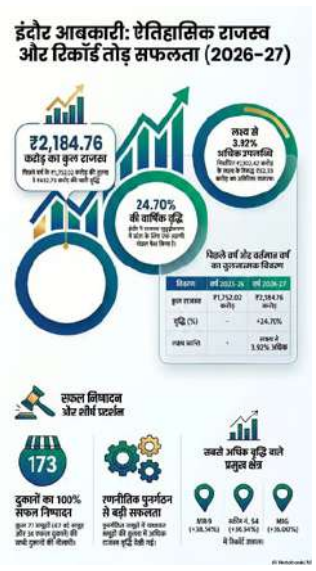

राजस्व संबंधी प्रमुख उपलब्धियां वर्ष 2025–26 के 1752.02 करोड़ की तुलना में 432.73 करोड़ की वृद्धि (24.70%) •वर्ष 2026–27 के निर्धारित लक्ष्य 2102.42 करोड़ के विरुद्ध 82.33 करोड़ अधिक प्राप्त (3.92% अधिक)

प्रक्रिया की प्रमुख विशेषताएं

संपूर्ण प्रक्रिया ई-टेंडर एवं ई-टेंडर कम ऑक्शन के माध्यम से पारदर्शी रूप से संपन्न चरणबद्ध एवं सुव्यवस्थित रणनीति के माध्यम से अधिकतम प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित अंतिम चरणों में एकल दुकानों के माध्यम से शत-प्रतिशत निष्पादन सुनिश्चित किया गया। उल्लेखनीय राजस्व वृद्धि वाले प्रमुख समूह

स्कीम नं. 54 समूह – 36.34% वृद्धि

एम.आई.जी. समूह – 36.00% वृद्धि

एम.आर.-9 समूह – 38.54% वृद्धि

चंद्रगुप्त चौराहा (एम.आर.-10)– 37.13% वृद्धि

मांगलिया समूह – 25.94% वृद्धि

विशेष उल्लेखनीय उपलब्धि रेवती समूह में 20.98 करोड़ के विरुद्ध 32.10 करोड़ का ऑफर प्राप्त हुआ, जो लगभग 83.54% की वृद्धि है एवं जिले में उच्चतम वृद्धि के प्रमुख उदाहरणों में सम्मिलित है। अन्य जिलों की तुलना में इंदौर का प्रदर्शन इंदौर जिले द्वारा निर्धारित लक्ष्य से अधिक राजस्व प्राप्त किया गया है। वहीं, प्रदेश के अन्य जिलों में लगभग 753 करोड़ का राजस्व अभी शेष है, जबकि इंदौर जिले में प्रभावी रणनीति एवं प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के माध्यम से सभी दुकानों का शत-प्रतिशत निष्पादन सुनिश्चित किया गया है। इस प्रकार इंदौर जिले ने अन्य जिलों की तुलना में बेहतर एवं अग्रणी प्रदर्शन करते हुए राजस्व प्राप्ति में उल्लेखनीय सफलता अर्जित की है।

आत्मा के प्रकाश की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति हंसा चक्र के द्वारा होती है

हम जानते हैं कि हमारे सूक्ष्म शरीर में सात मुख्य चक्र होते हैं परन्तु इनके अतिरिक्त अन्य चक्र भी हैं जो हमें संतुलन प्रदान करने में सहायक होते हैं। इन्हीं में से एक है हंसा चक्र। हंसा चक्र दोनों भृकुटियों के मध्य में स्थित है। ये दोनों आँखों बाईं तथा दाईं ओर का द्योतक हैं। .....

कुण्डलिनी को विराट से सम्पर्क स्थापित करने के लिये हंसा चक्र से गुज़रना पड़ता है। हंसा चक्र पर ईड़ा और पिंगला के कुछ भाग की अभिव्यक्ति होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि ईड़ा और पिंगला की अभिव्यक्ति हंसा चक्र के माध्यम से होती है। तो हंसा चक्र वह चक्र है जो यद्यपि आज्ञा चक्र तक नहीं गया फिर भी जिसने इन दोनों नाड़ियों के कुछ सूत्र या कुछ भाग थामे हुए हैं और ये सूत्र नाक की ओर प्रवाहित होने लगते हैं, आपकी आँखों से, मुँह से और मस्तिष्क के माध्यम से इनकी अभिव्यक्ति होने लगती है। आप जानते हैं कि विशुद्धि चक्र की सोलह पंखुड़ियों हैं जो आँख, नाक, जिह्वा, गला और दाँतों की देखभाल करती हैं परन्तु इनकी अभिव्यक्ति का काम हंसा चक्र के माध्यम से होता है।

हंसा चक्र जाग्रत होने पर सद्- सद् विवेक विकसित होता है। संस्कृत का एक सुन्दर श्लोक है कि हंस और बगुला दोनो श्वेत पक्षी हैं, तो

दोनो में अन्तर क्या है? यदि दूध में पानी मिला हो तो हंस उसमें से दूध पी जाएगा और पानी को छोड़ देगा परन्तु बगुले को दूध तथा पानी अलग करने का विवेक नहीं है। हंसा चक्र हमारी चेतना में मंगलमयता की अभिव्यक्ति का केन्द्र बिन्दु है। इसका अभिप्राय यह है कि हंसा चक्र के जाग्रत स्थिति में होने पर हम तुरन्त जान जाते हैं कि शुभ क्या है और क्या अशुभ है। हमें दैवी विवेक प्राप्त हो जाता है।

आत्मा के प्रकाश की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति इसी हंसा चक्र के द्वारा होती है। हंसा चक्र में चमकने वाला आपकी आत्मा का प्रकाश आपको विवेक प्रदान करता है तो आपमें स्वतः ही अनुभव की बुद्धि आ जाती है और आप जान जाते हैं कि ठीक रास्ता कौन सा है। एक बार जब यह बुद्धि पारदर्शी हो जाती है और आप इसमें से हर चीज़ स्पष्ट देखने लगते हैं तो आपका मस्तिष्क भी पूर्णतया स्वच्छ हो जाता है।

आँखें तथा कान अब पूरे वातावरण में ऐसी अनुक्रिया प्रसारित करने लगते हैं कि आप केवल सुन्दर को ही ग्रहण करते हैं। एक बार जब आप ऐसा करना सीख जाते हैं तब आप कहते हैं हम आनन्द सागर में तैर रहे हैं। सागर तो वही है, पर अब आप उसके अन्दर की अमृत की सुन्दर बूँदों को प्राप्त कर लेते हैं और अन्य लोग डूबने से डरते रहते हैं। यही संसार है। इसी कारण लोग कहते हैं कि यह माया है, पर विवेक बुद्धि में माया नहीं रह जाती। हंसा चक्र के कार्यान्वित होने पर ही उत्थान संभव है। जब तक आपका हंसा चक्र कार्यान्वित नहीं होता, तब तक आपका आनन्द प्राप्त करना सम्भव नहीं। इस विश्वास के साथ कि इन बन्धनों को त्यागने में ही हमारा हित है, इनसे यदि हम छुटकारा पा लें तो आज्ञा चक्र खुल जाता है। हंसा चक्र का महानतम कार्य ... यह है कि यह आपके पूर्व कर्मफल को समाप्त करता है। पूर्व-कृत अपराध फल के भय से मुक्ति देता है । कीचड़ में जन्मे कमल की तरह आप सुन्दर होंगे और पूरे विश्व में सुन्दर सुगन्ध बिखरेंगे जब आपका हंसा चक्र जाग्रत हो जाएगा। ('सहज ब्रह्मविद्या' पुस्तक से साभार) अपने नज़दीकी सहजयोग ध्यान केंद्र की जानकारी आप टोल फ्री नंबर 1800 2700 800 से प्राप्त कर सकते हैं।

आर्थिक गडबडियों एवं वित्तीय अनियमितता के तीन प्रकरणों में सात ग्राम पंचायतों की जिला पंचायत सीईओ ने की वन टू वन सुनवाई

नवल किशोर कुशवाहा

कटनी। वित्तीय अनियमितता एवं आर्थिक गड़बड़ियों के प्रकरणों में जिला पंचायत की सीईओ सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर ने शुक्रवार को मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 के तहत तीन प्रकरणों में सात ग्राम पंचायतों की वन टू वन सुनवाई की। सुनवाई के दौरान जनपद पंचायत कटनी की ग्राम पंचायत हीरापुर कोड़ियां, जनपद पंचायत बड़वारा की ग्राम पंचायत बनगवा एवं जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा की सनकुई, खमतरा, इमलिया, लालपुर और बरही ग्राम पंचायतों के तत्कालीन सरपंच, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक,उपयंत्री एवं कार्यरत सरपंच, सचिव,ग्राम रोजगार सहायक और उपयंत्री आदि मौजूद रहे। जिला पंचायत की सीईओ सुश्री कौर ने ग्राम पंचायतों के पक्ष को अत्यंत धैर्यपूर्वक सुनते हुए प्रस्तुत दस्तावेजों एवं प्राप्त प्रतिवाद का गहन और सूक्ष्म रूप से अध्ययन किया। ग्राम पंचायतों की सुनवाई और अभिलेखों के परिशीलन के दौरान रीडर शाखा के प्रभारी अधिकारी पंकज नामदेव मौजूद रहे।

अंशकालीन कर्मचारियों को दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी किए जाने हेतु संघ ने मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री के नाम संयुक्त कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

नवल किशोर कुशवाहा

कटनी। मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ जिला शाखा कटनी के मीडिया प्रभारी अनिल पांडेय ने बताया कि आज दिनांक 17 अप्रैल को संघ प्रधान शाखा भोपाल के निर्देशानुसार कटनी जिले के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन के समस्त विभागों में कार्यरत अंशकालीन कर्मचारियोंको दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी की श्रेणी में किया जाने हेतु एक सूत्रीय मांग का मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री मध्य प्रदेश शासन के नाम का ज्ञापन श्रीमान संयुक्त कलेक्टर जितेंद्र पटेल को सौंपा गया शासन से मांग की गई है कि अंशकालीन कर्मचारी जो कि विगत 20 से 22 वर्षों से कार्यरत है और नियमित कर्मचारियों की भांति सेवाएं दे रहे हैं जिनको शासन मजदूरी आवंटन बजट के तहत कोषालय के द्वारा वेतन भुगतान किया जाता है जो कि आज महंगाई के दौर में अल्पवेतन में परिवार की जीवन यापन पालन पोषण करना कठिन हो गया है और आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है अतः संघ माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय वित्त मंत्री जी मध्य प्रदेश शासन से अनुरोध करता है कि उक्त माँग का सहानुभूति पूर्वक निराकरण करने की कृपा करें ज्ञापन संघ के जिलाध्यक्ष एवं प्रांतीय संगठन प्रचार सचिव पूर्णेश उइके अजय गौतम उप प्रांताध्यक्ष नीलेश पौराणिक अजीमुद्दीन शाह मनोज श्रीवास अमृत लाल दुबे भगीरथ तिवारी चंद्रमोहन गणेशन पिल्लई रामपाल सिंह अन्य ने सौंपा।

राजस्व एवं खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने की दुकानों की जांच कीड़े लगे काजू को मौके पर ही कराया नष्ट

नवल किशोर कुशवाहा

कटनी । जिले के नागरिकों को शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने हेतु कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देशानुसार राजस्व एवं खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम द्वारा कटनी के नारायणशाह मार्केट स्थित दुकानों की जांच की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवकी सोनवानी ने बताया कि संयुक्त टीम द्वारा न्यू ओम टेंडर्स एवं सिद्ध किराना दुकान की जांच की गई। जांच के दौरान न्यू ओम टेंडर्स में कीड़े लगे हुए लगभग पांच किलो काजू पाया गया। जिसे मौके पर ही नष्ट कराया गया और दुकान मालिक को सख्त हिदायत दी गई कि इस प्रकार की खाद्य सामग्री दुकान में विक्रय हेतु पाई गई तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही दुकान से काजू, बादाम व किशमिश के नमूने जांच हेतु लिए गए। इसके बाद टीम द्वारा सिद्ध किराना की जांच की गई। दुकान में मसाले, ड्राई फ्रूट का विक्रय होना पाया गया। मिलावट की आशंका पर दुकान से खसखस, कालीमिर्च एवं अंजीर के नमूने जांच हेतु लिए गए है। जांच हेतु लिये गये सभी खाद्य पदार्थों के नमूने राज्य जांच खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेजे जा रहे हैं। रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। टीम ने बताया कि इस तरह की कार्यवाई निरंतर जारी रहेगी।

बीच बाजार में शराब पर बवाल: स्कूल-मंदिर के पास ठेका खुला, महिलाओं का फूटा गुस्सा-दुकान बंद!

महेन्द्र मालवीय
रणजीत टाईम्स

बुरहानपुर जिले में बीच बाजार स्थित शराब दुकान को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। स्कूल, मंदिर और रहवासी क्षेत्र के बीच खुले इस ठेके के खिलाफ क्षेत्रवासियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं और पुरुषों ने एकजुट होकर ठेकेदार के खिलाफ जमकर हंगामा किया, जिससे इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। जानकारी के अनुसार बाजार क्षेत्र में खुलेआम शराब परोसी जा रही थी, जिसे देखकर स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क उठा। विरोध के दौरान भाजपा नेता वीरेंद्र तिवारी और शराब ठेकेदार आमने-सामने आ गए। स्थिति बिगड़ते देख मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया और तत्काल कार्रवाई करते हुए दुकान को बंद करवा दिया गया। प्रदर्शन में शामिल महिला संजीवनी महाजन ने स्पष्ट कहा कि स्कूल और मंदिर के पास शराब दुकान किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं लीलाबाई रतन भोई ने कहा कि यहां छोटे-छोटे बच्चे रहते हैं, ऐसे माहौल का उनके भविष्य पर गलत असर पड़ेगा। उन्होंने यह भी आशंका जताई कि शराब के कारण परिवारों में विवाद बढ़ सकते हैं। यमुना बाई ने दो टूक शब्दों में कहा कि शराब दुकान गांव से कम से कम 5 किलोमीटर दूर होनी चाहिए और वे किसी भी कीमत पर इसे यहां नहीं खुलने देंगी। वहीं वीरेंद्र तिवारी ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि क्षेत्रवासियों का विरोध पूरी तरह जायज है और यहां शराब दुकान नहीं खुलने दी जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ठेकेदार अमरीशपुरी ने निर्णय नहीं बदला, तो दुकान के सामने धरना देकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। शाहपुर थाना के एसआई लोवंशी ने बताया कि महिलाओं के हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया गया। उन्होंने कहा कि मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी जा रही है और शराब दुकान की अनुमति की जांच की जाएगी। अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह पूरा मामला एक बार फिर प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। फिलहाल क्षेत्रवासियों का स्पष्ट संदेश है--रहवासी इलाके में शराब दुकान किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी।

माई नदी घाट पर चला विशेष सफाई अभियान, जल संरक्षण के साथ-साथ दिया गया स्वच्छता का संदेश

जल संरचनाओं को स्वच्छ रखने का लिया संकल्प

कटनी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 एवं जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत नगर पालिक निगम कटनी द्वारा स्वच्छता और जल संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न गतिविधियां सतत संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को वार्ड क्रमांक 14, राजीव गांधी वार्ड स्थित माई घाट पर विशेष सफाई अभियान आयोजित किया गया, जिसमें जल स्त्रोतों की स्वच्छता के साथ-साथ नागरिकों को जागरूक करने पर विशेष जोर दिया गया। निगम प्रशासन द्वारा आयोजित इस अभियान का मुख्य उद्देश्य शहर को स्वच्छ, स्वस्थ एवं पर्यावरण अनुकूल बनाना है। अभियान के तहत जनसहयोग के माध्यम से श्रमदान किया जाकर घाट के जल में तैर रहे प्लास्टिक एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित कर तसले के माध्यम से वाहन तक पहुंचाकर सुरक्षित निपटान हेतु भेजा गया। इस दौरान उपस्थित जनों द्वारा घाट परिसर में फैली गंदगी की व्यापक सफाई की गई।

स्वच्छ भारत मिशन के नोडल अधिकारी आदेश जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण के निर्धारित मानकों के अनुरूप नगर निगम द्वारा जल स्त्रोतों की सफाई, कचरा प्रबंधन एवं जन जागरूकता से संबंधित गतिविधियों को प्राथमिकता दी जा रही है। जल गंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से नागरिकों को जल स्त्रोतों के संरक्षण, प्लास्टिक के उपयोग में कमी एवं स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित नागरिकों, विद्यार्थियों एवं सामाजिक संगठनों द्वारा नदी-तालाबों को स्वच्छ एवं प्लास्टिक मुक्त बनाए रखने का सामूहिक संकल्प लिया गया। इस अवसर पर तिलक महाविद्यालय के प्राध्यापकों, छात्र-छात्राएं एवं निगम की सहयोगी संस्था ओम साईं विजन की टीम की सक्रिय सहभागिता रही। उल्लेखनीय है कि नगर निगम द्वारा इस प्रकार के अभियान निरंतर संचालित कर स्वच्छ सर्वेक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ-साथ जल संरक्षण की दिशा में भी सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं।

नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा अंतर्गत जागरूकता गतिविधियों का हुआ आयोजन

नवल किशोर कुशवाहा

कटनी । कलेक्टर आशीष तिवारी के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से नारी शक्ति वंदन अधिनियम के सम्बन्ध में आमजन को अवगत कराने निरंतर जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में परियोजना रीठी अंतर्गत ग्राम देवगांव के आंगनवाड़ी केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में वार्ड पंच श्रीमती अंजनी यादव एवं श्रीमती सुमन नामदेव का सम्मान किया गया। इस अवसर पर सरपंच श्री अक्षय राय उपस्थित रहे। वहीं परियोजना बहोरीबंद अंतर्गत परियोजना अधिकारी सतीश पटेल के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा अंतर्गत जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को नारी शक्ति वंदन अधिनियम की जानकारी दी गई। नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का संदेश घर-घर पहुचाने का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में परियोजना अधिकारी श्रीमती विद्या पाण्डेय के नेतृत्व में परियोजना मुड़वारा अंतर्गत ग्राम गुलवारा में रैली एवं शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया।

कार्यस्थलों पर संगठित धर्मांतरण का षड्यंत्र?

नासिक की घटना एक गंभीर चेतावनी

अभी तक समाज में 'लव जिहाद' और 'धर्मांतरण जिहाद' जैसे शब्द चर्चा में थे, किंतु महाराष्ट्र के नासिक से सामने आए मामले ने 'कार्पोरेट जिहाद' (व्यावसायिक जिहाद) के एक नए और सुनियोजित संकट को उजागर किया है। एक प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान में जिस प्रकार महिला कर्मचारियों का मानसिक, शारीरिक और धार्मिक उत्पीड़न किया गया, वह सभ्य समाज के लिए अत्यंत चिंताजनक है।

पदों का दुरुपयोग और शोषण की कार्यप्रणाली

इस प्रकरण की सबसे भयावह बात यह है कि इसमें संस्थान के उच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों, जैसे दल नायक (टीम लीडर) और कार्मिक प्रबंधक (HR मैनेजर) ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया।

»» **प्रलोभन और दबाव:** पदोन्नति और वेतन वृद्धि का लालच देकर युवतियों को प्रभावित किया गया।

»» **धार्मिक अपमान:** हिंदू देवी-देवताओं और प्रतीकों का निरंतर अपमान कर कर्मचारियों के मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया गया।

»» **अमानवीय कृत्य:** शाकाहारी युवतियों को गोमांस खाने और संस्थान परिसर में नमाज पढ़ने के लिए विवश किया गया।

भेष बदलकर सत्य का पता लगाना

जब पीड़ितों की शिकायतों को संस्थान के भीतर अनसुना कर दिया गया, तब पुलिस प्रशासन ने सराहनीय तत्परता दिखाई। महिला पुलिसकर्मियों ने भेष बदलकर संस्थान के भीतर प्रवेश किया और अपराधियों की गतिविधियों का प्रत्यक्ष साक्ष्य जुटाया। लगभग 40 स्थानों के चलचित्र (CCTV फुटेज) खंगालने के बाद यह स्पष्ट हुआ कि यह कोई सामान्य अपराध नहीं, बल्कि एक संगठित सिंडिकेट है।

'वीकेंड ट्रिप' के नाम पर जालसाजी

जाँच में यह भी सामने आया कि अवकाश के दिनों में भ्रमण (ट्रिप) के नाम पर कर्मचारियों को जल क्रीड़ा उद्यानों (वॉटर पार्क) और विश्राम गृहों (रिसॉर्ट्स) में ले जाया जाता था। वहाँ उन्हें असुरक्षित अनुभव कराकर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता था, ताकि वे मानसिक रूप से टूट जाएं और धर्मांतरण के लिए तैयार हो जाएं।

न्यायिक कार्रवाई और सामाजिक सुरक्षा

वर्तमान में दानिश शेख, तौसीफ अत्तर, रजा मेमन सहित सात आरोपियों को बंदी बनाया जा चुका है। विशेष जाँच दल (SIT) इस मामले की गहराई से तहकीकात कर रहा है। 18 से 25 वर्ष की आयु वर्ग की युवतियों को निशाना बनाना यह दर्शाता है कि यह षड्यंत्र नई पीढ़ी की पहचान मिटाने के लिए रचा गया था। नासिक की यह घटना केवल एक आपराधिक मामला नहीं है, बल्कि यह उन सभी संस्थानों के लिए चेतावनी है जहाँ बाहरी चमक-धमक के पीछे कट्टरपंथी विचारधारा का पोषण हो रहा है। प्रशासन को चाहिए कि वह दोषियों को कठोरतम दंड दे, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति किसी की धार्मिक आस्था और गरिमा के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस न कर सके। साथ ही, व्यावसायिक जगत को भी अपनी भर्ती प्रक्रिया और कार्य-संस्कृति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

यौन उत्पीड़न के आरोपित सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक को सुप्रीम कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक को अग्रिम जमानत दे दी। आरोपित पर एक महिला कर्मचारी का यौन उत्पीड़न करने और उसे और उसके पति को आपराधिक मामले में फंसाने की कोशिश करने का आरोप है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कोच्चि स्थित साफ्टवेयर कंपनी चलाने वाले कक्कनाड निवासी 50 वर्षीय वेणु गोपालकृष्णन को जांच में पूर्ण सहयोग देने का निर्देश दिया।

पीठ ने कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आरोपित राहत पाने का हकदार है। इसलिए, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और अपीलकर्ता के संबंध में हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हैं। पीठ ने कहा कि गोपालकृष्णन अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करें और किसी भी तरह से गवाहों को प्रभावित न करें या रिकार्ड में मौजूद सामग्री के साथ छेड़छाड़ न करें।

अमानक बीज मामले में सख्ती

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह के निर्देश पर नूनहेन्स कंपनी के खिलाफ FIR

मध्य प्रदेश के धार और खरगोन जिले के किसानों ने करेला फसल में हुए भारी नुकसान को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। किसानों ने बताया कि अमानक बीज और रोपे के कारण उनकी फसल बर्बाद हो गई, जिससे उन्हें बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। किसानों के अनुसार, उन्होंने नवंबर 2025 में विभिन्न नर्सरियों और कृषि सेवा केंद्रों से बीज और रोपे खरीदे थे। लेकिन बुआई के बाद फसल में सही उत्पादन नहीं हुआ। करेला के फल छोटे रह गए, पीले होकर गिरने लगे और उत्पादन में भारी गिरावट आई। इससे किसानों की आय पर सीधा असर पड़ा।

नुन्हेम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एफआईआर दर्ज

किसानों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे किसानों की आजीविका पर सीधा प्रहार बताया। उन्होंने अधिकारियों को तुरंत निर्देश दिए कि प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिलाया जाए और दोषी कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मंत्री के निर्देशों के बाद प्रशासन ने तेजी से कार्रवाई करते हुए धार जिले के मनावर थाने में संबंधित कंपनी नुन्हेम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता, आवश्यक वस्तु अधिनियम और बीज अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

अमानक बीज की फरवरी 2026 में की थी शिकायत

जांच में प्रारंभिक तौर पर यह सामने आया है कि किसानों को अमानक बीज और उन्हीं से तैयार रोपे प्रमाणित बताकर बेचे गए थे। इससे उनकी फसल को गंभीर नुकसान पहुंचा। किसानों ने पहले भी फरवरी 2026 में इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद विभागीय जांच कराई गई थी। मंत्री ने स्पष्ट कहा कि यह सिर्फ फसल खराब होने का मामला नहीं है, बल्कि किसानों की मेहनत, पूंजी और विश्वास से जुड़ा मुद्दा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए।

MP में हर चौथी MSME इकाई की मालिक महिला, राज्य में 8.87 लाख लघु उद्योग

देश में महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर चल रही बहस के बीच महिलाओं की आर्थिक भागीदारी से जुड़े आंकड़े नई तस्वीर पेश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ी है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक राज्य में अब हर चौथी MSME इकाई महिला उद्यमियों के नेतृत्व में संचालित हो रही है। यह बदलाव न केवल महिलाओं की आत्मनिर्भरता को दर्शाता है, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में उनके बढ़ते योगदान को भी रेखांकित करता है।

एमपी में 8.87 लाख MSME

28 फरवरी 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल 8,87,087 पंजीकृत MSME इकाइयां हैं। इनमें से 2,28,959 इकाइयों का संचालन महिलाएं कर रही हैं। यानी प्रदेश की लगभग हर चौथी MSME इकाई महिला उद्यमियों के हाथ में है, जो आर्थिक सशक्तिकरण का मजबूत संकेत है।

6 साल में 6 गुना बढ़ा महिला रोजगार

महिला उद्यमियों की बढ़ती संख्या का असर रोजगार पर भी साफ दिखाई दे रहा है। वर्ष 2020-21 में जहां MSME क्षेत्र में 1,53,493 महिलाएं कार्यरत थीं, वहीं 2026 तक यह संख्या बढ़कर 10,07,995 हो गई है। यह छह गुना से अधिक की वृद्धि दर्शाती है कि महिलाएं न केवल खुद आगे बढ़ रही हैं, बल्कि अन्य महिलाओं को भी रोजगार दे रही हैं।

उद्यम पोर्टल से मिली गति

वर्ष 2020-21 में उद्यम पोर्टल शुरू होने के बाद महिला उद्यमियों की संख्या में तेजी आई। उस समय 14,239 महिला स्वामित्व वाले MSME थे। 2022-23 में यह बढ़कर 2,07,795 और 2023-24 में 7,44,746 तक पहुंच गई। 2025-26 में यह संख्या 2,28,959 पर दर्ज की गई है।

राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ रहा महिलाओं का दबदबा

देशभर में भी महिला उद्यमिता तेजी से आगे बढ़ रही है। उद्यम पोर्टल पर अब तक 3.07 करोड़ महिला नेतृत्व वाले MSME पंजीकृत हो चुके हैं। महाराष्ट्र MSME पंजीकरण में अग्रणी है, जबकि महिला नेतृत्व वाले उद्यमों में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर है। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु भी इस सूची में मजबूत स्थिति में हैं।

आर्थिक सशक्तिकरण की नई तस्वीर

एमपी के ये आंकड़े बताते हैं कि महिलाएं अब सिर्फ घर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि व्यवसाय और उद्योग में भी अपनी मजबूत पहचान बना रही हैं। यह बदलाव नारी शक्ति के सशक्त और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ते कदम को दर्शाता है।

भोपाल एम्स में लापरवाही का बड़ा खुलासा! नवजात कक्ष में चूहे, वार्डों में कॉकरोच... वीडियो से मचा हड़कंप

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल एक बार फिर गंभीर लापरवाही को लेकर सवालों के घेरे में है। अस्पताल के नवजात शिशु कक्ष में चूहों की मौजूदगी और वार्डों के बाहर कॉकरोच दिखने का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है।

बताया जा रहा है कि जिस जगह नन्हीं जिंदगियों को सबसे ज्यादा सुरक्षा और स्वच्छता की जरूरत होती है, वहीं गंदगी और लापरवाही का आलम देखने को मिल रहा है। नवजात शिशुओं के लिए यह स्थिति बेहद खतरनाक मानी जा रही है। वीडियो सामने आने के बाद मरीजों के परिजनों में डर और गुस्सा दोनों देखने को मिल रहे हैं। उनका कहना है कि बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और अस्पताल प्रशासन इस पर गंभीर नहीं दिख रहा। स्वास्थ्य व्यवस्था की यह तस्वीर कई बड़े सवाल खड़े कर रही है—क्या अस्पताल में साफ-सफाई की नियमित व्यवस्था नहीं है? क्या मरीजों की सुरक्षा को लेकर जिम्मेदार लोग लापरवाह हैं? विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह की गंदगी से संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ जाता है, जो नवजात बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। अब देखना होगा कि इस खुलासे के बाद प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, या फिर यह मामला भी अन्य घटनाओं की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा।

MP में विधानसभा की हारी सीटें जीतने के लिए भाजपा ने बनाई 'कलस्टर-रणनीति', दिग्गज नेताओं को दी जिम्मेदारी

भोपाल। मध्य प्रदेश में 2028 में संभावित विधानसभा चुनाव में भाजपा उन सीटों को भी जीतने के लिए विशेष रणनीति बना रही है, जिन पर जनसंघ के समय से लेकर अब तक वह कम ही जीती है। ऐसी कई सीटों को चिह्नित कर उसने न सिर्फ संगठनात्मक गतिविधियों को अभी से बढ़ा दिया है बल्कि तीन-चार गांवों का कलस्टर बनाकर उनकी जिम्मेदारी दिग्गज नेताओं को दी है। उन्हें हार के कारणों का अध्ययन करने और उन्हें दूर करने के लिए मजबूत रणनीति बनाने को कहा गया है। ऐसी कई सीटों पर कांग्रेस अपने जिन दिग्गज नेताओं के प्रभाव के कारण मजबूत है, उनका किला भी भेदने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। ऐसी सीटों में खरगोन जिले की अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित भगवानपुरा सीट पर कांग्रेस या निर्दलीयों का दबदबा रहा है। धार जिले की कुक्षी सीट भी परंपरागत रूप से कांग्रेस के पक्ष में रही है। खरगोन जिले की अनुसूचित जाति वर्ग के लिए सुरक्षित भीकनगांव सीट पर भी भाजपा को कभी सफलता नहीं मिली। सीधी जिले की चुरहट सीट भी कांग्रेस का गढ़ रही है।

पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की इस परंपरागत सीट पर वर्ष 1993 और 2018 को छोड़कर कभी भी भाजपा नहीं जीती। एक बार 1967 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी भी जीती। मुस्लिम बहुल भोपाल उत्तर सीट पर भाजपा सिर्फ 1993 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद के राजनीतिक माहौल में मतों के ध्रुवीकरण के लाभ के चलते जीती। 2018 में फातिमा रसूल सिद्दीकी के रूप में प्रदेश में एकमात्र मुस्लिम उम्मीदवार को उतारकर भी भाजपा सफल न हो सकी। छिंदवाड़ा जिले की चौरई सीट लंबे समय से कांग्रेस, विशेषकर कमल नाथ परिवार के प्रभाव क्षेत्र में रही है।

मायावती का बड़ा हमला
सपा-कांग्रेस को घेरा ?

पिछड़ों के हक पर गिरगिट की तरह रंग बदल रहे दल, आरक्षण के नाम पर सिर्फ छलावा! बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा) पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये दल एससी, एसटी और ओबीसी समाज के संवैधानिक अधिकारों के मुद्दे पर लगातार अपना रुख बदलते रहे हैं और अब महिला आरक्षण के नाम पर भी राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। मायावती ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में इन वर्गों के आरक्षण को पूरी तरह लागू करने की दिशा में कभी ठोस पहल नहीं की।

OBC आरक्षण के संदर्भ में मंडल आयोग की सिफारिशों का जिक्र

मिली जानकारी के मुताबिक, उन्होंने ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में मंडल आयोग की सिफारिशों का जिक्र करते हुए कहा कि इसे लागू कराने का श्रेय बसपा के प्रयासों और पूर्व प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह की सरकार को जाता है। सपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछड़े मुस्लिमों को ओबीसी का लाभ देने संबंधी आयोग की रिपोर्ट को सपा सरकार ने लंबे समय तक लागू नहीं किया, जबकि बसपा सरकार ने 1995

में इसे लागू किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि अब वही सपा राजनीतिक स्वार्थ के तहत महिलाओं के लिए अलग आरक्षण की बात कर रही है।

परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर होना चाहिएः मायावती

महिला आरक्षण पर मायावती ने कहा कि परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कांग्रेस सत्ता में होती, तो वह भी भाजपा की तरह ही कदम उठाती। अपने बयान में उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि देश में एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिम समाज के वास्तविक हितों को लेकर कोई भी पार्टी पूरी तरह गंभीर नहीं रही है। उन्होंने इन वर्गों से अपील की कि वे किसी के बहकावे में न आएं और अपने हितों को ध्यान में रखते हुए आत्मनिर्भर बनें।

पंजाब में टला रेल रोको आंदोलन
सरकार को किसानों ने दिए तीन दिन

पंजाबः सरकारी देरी से नाराज़ किसानों ने अपने प्रस्तावित रेल रोको आंदोलन को फिलहाल तीन दिन के लिए टाल दिया है। यह फैसला राज्य सरकार द्वारा समय मांगे जाने के बाद लिया गया है।

किसान नेताओं का कहना है कि गेहूं की खरीद में हो रही देरी से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने केंद्र और पंजाब सरकार से मांग की है कि तुरंत खरीद प्रक्रिया शुरू की जाए, ताकि किसानों की फसल सुरक्षित रह सके और उन्हें उचित मूल्य मिल सके। किसानों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि तीन दिन के भीतर उनकी मांगों पर ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो रेल रोको आंदोलन फिर से शुरू किया जाएगा और इसे बड़े स्तर पर किया जाएगा। किसान संगठनों का आरोप है कि हर साल खरीद को लेकर आश्वासन दिया जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर समस्याएं बनी रहती हैं। इस बार भी वही स्थिति देखने को मिल रही है, जिससे किसानों में नाराज़गी बढ़ती जा रही है।

फिलहाल सभी की नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी है। अगर तय समय में समाधान नहीं निकला, तो पंजाब में एक बार फिर बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है।

सिर्फ विशाल बाजार बनना नहीं, वैश्विक ताकत बनने की है असली चुनौती

दुनिया इस समय एक अजीब दौर से गुजर रही है। कहीं युद्ध चल रहे हैं, कहीं युद्ध की तैयारी है और कहीं बिना युद्ध के भी सब कुछ प्रभावित हो रहा है। पहले ऐसा माना जाता था कि अगर बाजार खुला रहेगा तो अर्थव्यवस्था चलती रहेगी। हालांकि अब यह भरोसा कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि आज का संकट केवल व्यापार का नहीं है, बल्कि सप्लाई, सुरक्षा और भरोसे का भी है। ऐसे समय में भारत को यह समझना होगा कि वह सिर्फ एक बड़ा बाजार बनकर आगे नहीं बढ़ सकता। तब तो और नहीं जब बाजार एक ताकत के कब्जे में रहे।

इससे अर्थव्यवस्था कभी भी डगमगा सकती है। भारत केवल एक बड़ा उपभोक्ता देश बनता जा रहा है। हमारे पास युवा आबादी है, तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था है और दुनिया की बड़ी कंपनियों के लिए एक बड़ा बाजार है, लेकिन क्या केवल उपभोक्ता बनकर कोई देश मजबूत बन सकता है? अगर उत्पादन, तकनीक, ऊर्जा और अन्य जरूरी संसाधनों के मामले में हमारी बाहरी निर्भरता बनी रहेगी तो थोड़ी सी वैश्विक हलचल भी हमें हिला सकती है और इसका उदाहरण आज हमारे सामने है। युद्धों का सबसे पहले असर ऊर्जा पर पड़ता है। तेल और गैस की कीमतें बढ़ती हैं। सप्लाई में रुकावट आती है। इसका प्रभाव आम आदमी की जेब पर पड़ता है, लेकिन संकट यहीं खत्म नहीं होता। एक और बड़ा खतरा है डिजिटल ढांचे का। आज हमारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा इंटरनेट, डाटा और क्लाउड पर टिका है। बैंकिंग से लेकर सरकारी सेवाएं, पढ़ाई से लेकर व्यापार सब कुछ डिजिटल हो चुका है। ऐसे में अगर युद्ध के कारण डाटा सेंटर प्रभावित होते हैं, इंटरनेट के रास्ते बाधित होते हैं या साइबर हमले बढ़ते हैं, तो पूरी व्यवस्था ठप हो सकती है। स्वास्थ्य सेवाएं भी इससे अछूती नहीं हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि अस्पताल केवल डाक्टर और दवाओं से चलते हैं, लेकिन सच यह है कि वे वैश्विक सप्लाई चेन पर निर्भर होते हैं। उदाहरण के लिए एमआरआइ मशीन में इस्तेमाल होने वाली हीलियम गैस एक ऐसी विशेष गैस है, जो मशीन को सही तापमान पर काम करने में मदद करती है। भारत अपनी हीलियम जरूरत का बड़ा हिस्सा कतर से आयात करता है। यह देश दुनिया के बड़े हीलियम उत्पादकों में से एक है। अगर युद्ध के कारण वहां से उसकी सप्लाई बाधित होती है तो इसका असर सीधे हमारे अस्पतालों पर पड़ेगा। जांच में देरी के साथ इलाज महंगा हो सकता है और कई जगहों पर सेवाएं बाधित हो सकती हैं। इसका मतलब यह है कि युद्ध का असर आम नागरिक के इलाज तक पर पड़ता है।

यही वह स्थिति है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि विकास का मतलब केवल बाजार नहीं हो सकता।

बाजार जरूरी है, पर वह सब कुछ नहीं कर सकता। बाजार वहां जाता है, जहां फायदा होता है, लेकिन देश को उन जगहों पर भी काम करना पड़ता है, जहां फायदा तुरंत नहीं दिखता, मगर उन क्षेत्रों की महत्ता कम नहीं। जैसे बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा और रिसर्च। अगर इन क्षेत्रों को पूरी तरह बाजार के भरोसे छोड़ दिया जाए, तो असमानता बढ़ेगी और देश कमजोर पड़ेगा। इसी कारण जवाहरलाल नेहरू ने समझा था कि एक नए देश को खुद को मजबूत बनाने के लिए सरकार की भूमिका जरूरी है। उन्होंने उद्योग, बिजली, वैज्ञानिक संस्थान और सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दिया ताकि देश अपने पैरों पर खड़ा हो सके। उनका उद्देश्य केवल आर्थिक विकास नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाना था, जो संकट के समय भी टिक सके। बाहरी दुनिया के साथ तालमेल की कड़ी मानी जाने वाली विदेश नीति में भी आज असंतुलन दिखता है। एक ओर हम स्वतंत्र निर्णय की बात करते हैं, लेकिन कई बार व्यवहार में झुकाव अधिक स्पष्ट दिखता है। पश्चिमी देशों के साथ बढ़ती नजदीकी जरूरी हो सकती है, पर अगर संतुलन बिगड़ता है, तो हमारे पारंपरिक संबंध कमजोर हो सकते हैं। विदेश नीति की ताकत इसी में होती है कि वह सभी पक्षों से संबंध बनाए रखे। असंतुलन यह भी है कि विदेश नीति और आर्थिक नीति के बीच हमेशा स्पष्ट तालमेल नहीं दिखता। हम वैश्विक मंचों पर स्वतंत्र रुख की बात करते हैं, लेकिन व्यापार और तकनीक के मामलों में कुछ खास देशों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। यह स्थिति भविष्य में जोखिम पैदा कर सकती है, खासकर तब जब दुनिया पहले से ही अनिश्चितता से भरी हो। एक मजबूत विदेश नीति वही होती है, जो हर परिस्थिति में देश के हितों की रक्षा करे और किसी एक दिशा पर अत्यधिक निर्भरता से बचे। आज दुनिया कई खेमों में बंटी हुई है। बड़े देश अपने हिसाब से फैसले ले रहे हैं। ऐसे में भारत को सावधानी से चलना होगा। हमें सभी से संबंध रखने हैं, लेकिन किसी एक पर पूरी तरह निर्भर नहीं होना है। यह संतुलन हमारी ताकत हो सकता है। आज आत्मनिर्भरता का मतलब केवल कारखाने लगाना नहीं है। इसका अर्थ है कि हम जरूरी चीजों के लिए पूरी तरह विदेश पर निर्भर न रहें। हमें ऊर्जा के अलग-अलग स्रोत चाहिए, डिजिटल ढांचा अपने नियंत्रण में चाहिए, जरूरी दवाएं और मेडिकल उपकरण देश में बनें। हमें तकनीक में भी क्षमताएं बढ़ानी होगी।